(b) the number of casual workers who have completed more than two years service in muster roll as casual labourers but have not so far been made regular (division-wise) alongwith reasons in each case; and

(c) whether Government have formulated any time-bound programme for making them regular; if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMAD USMAN ARIF): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) No. In C.P.W.D. casual labourers are appointed on regular posts which are required to be filled by Direct Recruitment, subject to aavilability of vacancies and fulfilment of requisite conditions by the workers.

संसद् सदस्यों को जनरल पूल से आवास आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1244. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों को जनरल पूल से किन दिशा-निर्देशों के आधार पर आवास आवंटित किए जाते हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने संसद् सदस्यों को जनरल पूल से टाइप vi से टाइप viii के बंगले आवंटित किए गए ; और

(ग) क्या उन बंगलों के आवंटन में दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) संसद् सदस्यों को सामान्य पूल आवास के आवंटन के सम्बन्ध में सरकार ने मई, 1984 में निम्नलिखित मार्ग-निर्देशन निर्धारित किये :—

(i) भविष्य में मंत्रिमंडल आवास समिति के अनुमोदन के बिना किसी भी संसद् सदस्य को सामान्य पूल से टाइप viii के बंगलों का आवंटन नहीं किया जाएगा ।

(ii) निम्नलिखित मार्ग-निर्देशनों के अनुसार सामान्य पूल आवास संसद् सदस्यों को आवंटित करने के लिए निर्माण और आवास मंत्री को प्राधिकृत किया जाए :—

(क) जो सदस्य, भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष/सभापति, भूतपूर्व न्यायाधीश, भूतपूर्व राजदूत हैं, उन्हें उपलब्धता के आधार पर टाइप–vii के वर्ग के मकान का आवंटन किया जाएगा ।

(ख) जो सदस्य राज्यों में मंत्री/विधान सभा के अध्यक्ष/सभापति पी०सी०सी० अध्यक्ष थे या जो अपनी नियत अवधि या इससे अधिक की अवधि के लिए संसद् के लिए चुन लिए गए हैं उन्हें टाइप–vi वर्ग के मकान आवंटित किए जा सकते हैं ।

(ग) अन्य सदस्यों को टाइप–v वर्ग के मकान अर्थात् नार्थ/साउथ एवेन्यू आदि में फ्लैट आवंटित किए जा सकते हैं ।

(ख) 14 (चौदह) ।

(ग) तेरह मामलों में आवंटन मार्ग-निर्देश निर्धारित करने की तारीख से पहले किए गए थे । केवल एक मामले में अर्थात श्री दीपेन घोष, संसद सदस्य (राज्य सभा) के मामले में टाइप VII के बंगला नं० 8, तीन मूर्ति लेन का आवंटन मार्ग निर्देशनों में ढील देकर इस विचार से किया गया था कि वे संसद् में

सी० पी० आई० (एम०) संसदीय दल के नेता हैं। अन्य मामले में बंगला नं० 3, कुशक रोड, श्री एम० पी० कौशिक, संसद् सदस्य (राज्य सभा) को आवंटित करने की पेशकश की है। तथापि, संसद् सदस्य को बंगले का कब्जा अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि यह बंगला श्री दयानन्द सहाय, भूतपूर्व संसद् सदस्य के अनधिकृत कब्जे में है।

Statement of Shri M. P. Birla regarding price hike of levy cement

1245. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Telegraph of the 11th July, 1984 (Calcutta) wherein Shri M. P. Birla, Chairman, Birla Jute and Industries Ltd., had given a statement to the effect that Government would raise the price of levy cement; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO): (a) Yes, Sir.

(b) The Cement Manufacturers Association had urged the Government for escalation by Rs. 88.75 due to increase in input costs like coal, power, freight on coal and wages. The Government after a study by the Bureau of Industrial Costs & Prices has allowed an increase of Rs. 40 per tonne only with effect from 18-7-84 together with marginal reduction in levy quota.

Suspension of training to seamen at Naolakhi and Visakhapatnam

1246. SHRI HUSEN DALWAI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have suspended the training which was given to the seamen at Naolakhi and Visakhapatnam on account of recession in the shipping industry;

(b) whether the recession in the shipping industry has adversely affected the future of seafare community; and

(c) if so, what step Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) to (c) As a result of the recession in the Shipping Industry an acute unemployment situation among Indian seamen has arisen. Government set up an Expert Committee under the Chairmanship of Admiral S. M. Nanda (Retired) to go into this question. One of the principal recommendations of this Committee has been, among others, that "no fresh recruitment and training to be resorted to till the trained candidates waiting for placement are fully absorbed." Accepting this recommendation, Government have suspended the pre-sea training in all the three pre-rating training establishments namely T. S. Bhadra, Mekhala and Naulakshi. The position of available jobs and seamen will be reviewed in 1985 and thereafter every year, if necessary.

Science Museum at Nagpur

1247. SHRI S. W. DHABE:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Council of Science Museum,